

आकाशवाणी ईटानगर

विधायी मामलों के मंत्री बामांग फेलिक्स ने आज विधान सभा में तिब्बती पुनर्वास नीति दो हजार चौदह को रखा। उन्होंने कहा कि विधान सभा की राय है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार सभी हितधारकों से विचार विमर्श और भारतीय संविधान के अनुसार मूल जनजातियों की अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखकर ही इसे लागू करेगी। इस विषय पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधायक पांगा बागे ने कहा कि विशाल वन क्षेत्र के चलते राज्य का केवल तेईस प्रतिशत भू-भाग में ही आबादी है और इसके मद्देनजर वर्तमान तिब्बती नागरिकों की पहचान के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था होनी चाहिए। विधायक तागे ताकी ने व्यापक विचार विमर्श की वकालत की। जबकि मारकियों तादों ने तिब्बती पुनर्वास नीति को संवेदनशील त्रूटिपूर्ण बताते हुए एक संयुक्त तदर्थ समिति बनाने का सुझाव दिया। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए राज्य सरकार से पहले लोक सभा में पास कराने का सुझाव दिया। विधान सभा में कुछ तिब्बती लोगों को एस टी सर्टिफिकेट देने का भी मुद्दा ऊठा। कांग्रेस विधायक नाबाम तुकी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा के अनमोदन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वे टी आर पी के खिलाफ नहीं है, लेकिन राज्य में इसे लागू करने के खिलाफ है। राज्य विधान सभा में कल चकमा - हाजोंग मुद्दे पर चर्चा होगी। आज विधानसभा में चार विधेयक पारित किये गए जिसमें अरुणाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक दो हजार सत्रह, अरुणाचल प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक दो हजार सत्रह, अरुणाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक और अरुणाचल राज्य सड़क नियमन एवं विकास विधेयक दो हजार सत्रह शामिल है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ईटानगर से बंदरदेवा तक राजमार्ग के लिए शेष पैकेज को दो हजार सत्रह - अट्ठारह के लिए मंत्रालय के वार्षिक योजना में शामिल किया जाएगा। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कल राज्यपाल बी डी मिश्रा को यह जानकारी दी गई। इससे पहले राज्यपाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्राथमिकता ए आधार पर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित मामलों पर ज्ञापन सौंपा।

केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक में राज्यपाल ने मंत्रालय से मुख्य परियोजना को मंजूरी मिलने और बजटरी सहायता सहित ईटानगर - बंदरदेवा सड़क के लिए शेष पैकेज पर प्रस्ताव की जानकारी दी।

वही केंद्रीय संपर्क राज्य मंत्री मनोज सिंहा के साथ हुई अलग बैठक में श्री मिश्रा ने मंत्री को राज्यभर में पड़ी ऑप्टिकल फॉइबर केबल कार्य की सुस्त प्रगति की ओर ध्यान केंद्रीय किया और सभी लंबित मामलों को सुलझाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने मंत्री से रेलतेल निगम लिमिटेड को अपने कार्य में तेजी लाने का निर्देश देने का भी आग्रह किया। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट संपर्क मुहैया कराना आज के समय की मांग है।

कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री वांकी लोवांग ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में कारगर सिद्ध हो रही है। आज ईटानगर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर जागरुकता कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ही ऋण प्रदान किया जाता है। उन्होंने जन शिकायतों का बैंक अधिकारियों से त्वरित निपटारा करने और नागरिकों से किसी अन्य कार्य के लिए मुद्रा लोन हेतु बैंक के प्राधिकारियों पर दबाव न बनाने की अपील की। श्री लोवांग ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रदेश में सकारात्मक असर हुआ है। सरकारी आकड़ों के अनुसार ज्यादातर लोगों द्वारा फिजुल खर्ची के बजाय अपने खातों में धन जमा करने से मुद्रा स्फीति में कमी आई है। श्री लोवांग ने मुद्रा लोन के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा चयनित उद्यमियों को पत्र प्रदान किया। उन्होंने केंद्र सरकार की वित्तीय समावेशन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसमें लोगों को बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को जोड़ने, प्रधानमंत्री बीमा योजना, मुद्रा लोन प्राप्त करने सहित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने कहा है कि जिला प्रशासन डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। ईटानगर में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि एक महीने के भीतर ईटानगर के आकाशदीप क्षेत्र को वाईफाई जोन में विकसित किया जायेगा। जिला उपायुक्त ने कहा कि व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन के लिए सभी सुविधा निशुल्क मुहैया कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के उद्यमी ऑन लाईन प्लेटफार्म पर अपना उत्पाद सरकार तथा अन्य लोगों को बेच सकेंगे। श्री धवन ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से उनके बिजनेस मॉडल के आधार पर किया जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने कल केरल में भाजपा एवं आर एस एस कार्यकर्ताओं की हत्या तथा उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी मोर्चा को सहयोग देने के लिए कल जनसुरक्षा पद यात्रा का आयोजन किया। इंदिरा गांधी पार्क स्थित टेनिस कोर्ट से शुरु हुई रैली विद्युत भवन के निकट जाकर संपन्न हुई। भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष - तापिर गाव के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में कई मंत्रियों विधायी सचिवों, विधायकों और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

अरुणाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कल वेस्ट कामेंग जिले के बोमडिला स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर में लिगल एड क्लीनिक का शुभारंभ किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव बुदी हाबुंग ने क्लीनिक का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बोमडिला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा वेस्ट कामेंग जिला डी एल एस ए के अध्यक्ष गोटे मेगा, वेस्ट कामेंग बार संघ के अध्यक्ष खामु देसिसों और कई वकील मौजूद थे।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण एवं जनजातिय मामला विभाग के सचिव ओनित पायांग ने गत रविवार को दोनी पोलो स्कूल फॉर हियरिंग एंड विजुएली इम्पेयरस् के छब्बीसवें स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूल के लिए बस को हरी झंडी दिखाई। बस को सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण एवं जनजातिय मामला विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया।
